● मुख्यमंत्री ने निर्माण इकाई लगाने के दिए निर्देश ● आईआईटी के सहयोग से नए पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे

यूपी में शुरू होगा ड्रोन निर्माण

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

आपदा राहत, कृषि, कानून-व्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में ड्रोन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में भी इसका निर्माण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश में ड्रोन निर्माण ईकाई लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

अपने सरकारी आवास पर उच्चाधिकारियों संग बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीआई संस्थानों में ड्रोन तकनीक के प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट व डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कराए जाएं। इसके लिए आईआईटी कानपुर का सहयोग लिया जाए। उन्होंने ड्रोन निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने और ड्रोन के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन अपनी पहुंच, उपयोग में आसानी के कारण दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साथ ही ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करना चाहती हैं। उन्होंने अधिकारियों से अन्य निवेशकों से भी संपर्क करने को कहा और सुझाव दिया कि डिफेंस कॉरिडोर इस उद्योग के लिए एक उपयोगी क्षेत्र हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नई नियमावली में ड्रोन के उपयोगकर्ताओं को उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र, रखरखाव प्रमाणपत्र, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, ऑपरेटर परमिट, छात्र दूरस्थ पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट प्रशिक्षक प्राधिकरण आदि जारी करने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए।

सुविधा: प्रदेश को आज सात नए इंटरनेट एक्सचेंज मिलेंगे

लखनऊ। यूपी में अब आठ इंटरनेट एक्सचेंज होंगे। अभी यूपी में सिर्फ नोएडा में एक इंटरनेट एक्सचेंज है। सात नए एक्सचेंज का लोकार्पण गुरुवार को केंद्रीय राज्यमंत्री-इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर व केंद्रीय राज्यमंत्री विधि एवं न्याय प्रो. एसपी सिंह बघेल आगरा में करेंगे। नए एक्सचेंज मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में होंगे।

तैयारी

प्रदेश के राजकीय पॉलीटेक्निक में नए पाठ्यक्रम शुरू कराने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स एक महीने में पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देकर उसे स्वीकृत भी करेगा। प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग इसके अध्यक्ष होंगे।

योजना

मुख्यमंत्री ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नगर विकास और आवास विभाग को नए शहरों की स्थापना के लिए अध्ययन करते हुए रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने एकेटीयू लखनऊ, मदन मोहन मालवीय तकनीकी विवि गोरखपुर और एचबीटीयू कानपुर व दो अन्य संस्थानों के सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की टीम बनाकर लाइट हाउस परियोजना का अध्ययन कराने को कहा।